

पत्रिका

कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश

(रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र संख्या : 819/1987-88)

वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ - 226 004

फोन : 0522-2242486 मोबाइल : 9415418566, 9335019355 फैक्स : 0522-2242486

E-mail : coldstorage@fcaoi.org Website : http://www.fcaoi.org

श्री जी.एस. धीरानी, सेक्रेट्री जनरल : 9839013400, 9335519355

मूल्य : 1/- ₹0 31 अगस्त, 2016 मासिक पत्रिका : अध्यक्ष : श्री महेन्द्र स्वरूप, ऐशबाग, लखनऊ। सचिव : श्री राजेश गोयल, आगरा। वर्ष : 13, अंक : 3

संगठन ही शक्ति है

बन्धुवर,

अगस्त महीना समाप्त हो चुका है। बिहार को छोड़ कर सारे आलू अधिक पैदा करने वाले प्रदेशों में, सामान्य से कुछ अच्छी ही वर्षा होने के समाचार मिले हैं। आशा है अभी सितम्बर माह में वर्षा और होगी और बिहार प्रदेश भी अपने वर्षा के घाटे को पूरा कर लेगा।

वर्षा को देखते हुए भविष्य में सभी प्रदेशों में अच्छी बुआई होने की आशा की जा रही है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सितम्बर माह



में भी अच्छी वर्षा होने की आशा की जाती है। यदि ऐसा रहा तो यह वर्षा जाड़े के मौसम में आने वाली आलू की फसल के लिए अच्छी रहेगी। परन्तु आलू की बुआई जरूर लेट हो सकती है।

इस समय आलू के भावों में मन्दी का महौल चल रहा है। 100 से 150 रूपए पैकेट की मन्दी देखी जा रही है। वैसे तो हर वर्ष भी अगस्त माह में मन्दी के हालात बन जाते हैं क्योंकि इसी माह के मध्य तक हासन, Meltupallium आदि पहाड़ी क्षेत्रों का आलू तैयार होता है। यह क्षेत्र दक्षिण के Karnataka में आता है जिसके कारण उत्तर भारत से आलू की लोडिंग जो कि दक्षिण भारत को होती है, उस पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, जिसकी वजह से आलू के रेट कम रहते हैं। कभी-कभी



तो यह आलू दक्षिण भारत से चल कर उत्तर भारत की मण्डियों में भी पहुँच जाता है। तब आलू के रेट में काफी हलचल रहती है। इस वर्ष इस आलू में बहुत ज्यादा मजबूती नहीं सुनी जा रही है और आशा की जाती है कि इसका असर 10/12 सितम्बर, 2016 तक काफी कम हो जाए। इधर शीतगृहों से बीज आलू की निकासी भी बहुत तेज बढ़ जाएगी। आलू की यह बीज निकासी खाने वाले आलू की निकासी को भी कम कर देती है। इस प्रकार खाने वाला आलू मण्डियों में कम पहुँच पाता है और मण्डी के भाव में सुधार आने लगता है।

हम जरूर आशा करते हैं कि भविष्य में आलू के भाव में सुधार रहेगा और स्थिति चिन्ताजनक नहीं रहेगी। परन्तु फिर भी हर भाव में थोड़ा थोड़ा आलू निकालते रहना ही उचित रहता है।

इस वर्ष उत्तर प्रदेश वा गुजरात के खास कर के, तथा अन्य सभी आलू उत्पादक प्रदेशों में नए शीतगृह बहुत तेजी से बन रहे हैं। कुछ तो नए शीतगृह होंगे और कुछ अपना नया चेम्बर जोड़ेंगे। शीतगृह वालों को चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आलू का उत्पादन भी बहुत तेज बढ़ रहा है और करीब उसी अनुपात में आलू की खपत भी बढ़ रही है। इस लिए भविष्य में और अधिक शीतगृहों की आवश्यकता रहेगी फिर भी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए हमें अपने खर्चों पर लगातार निगाह रखनी पड़ेगी।

शीतगृहों में मुख्य खर्चा बिजली का होता है। हमने देखा है कि अनेक शीतगृह ऐसे हैं जो बिजली के खर्च का सही अनुमान ही नहीं लगा पाते, उस का मुख्य कारण है उनके पास पुरानी मशीनें वा इन्सुलेशन की बहुत ही कमजोर वा दयनीय स्थिति है जिसकी वजह से बिजली खर्च बहुत ज्यादा आता है। हमें हर हालत में अपने इन्सुलेशन पर ध्यान देना होगा। वरना भविष्य में हम होने वाले Competition में पिछड़ जायेंगे।

बीस साल से पुराने लगे हुए इन्सुलेशन चाहे वह फाइबर ग्लास वा थर्मोकोल के हो, बेहद कमजोर हो जाते हैं। जगह जगह चूहे काट कर उन्हें और बर्बाद कर देते हैं। इन्सुलेशन का दिवाल से चिपके रहना करीब करीब खत्म हो जाता है।

इसलिए नए सिरे से इन्सुलेशन करवाना भी उचित हो सकता है। थर्मोकोल (Thermocole) के केस में, बीस डैन्सिटी (Density) से कम का थर्मोकोल ना लगाए तो अच्छा रहेगा।

इन्दौर मीटिंग के सम्बन्ध में :

कृपया ध्यान दें कि फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया वा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की वार्षिक मीटिंग (Annual General Meeting) इन्दौर, मध्य प्रदेश में आयोजित की जा रही है, जिस में हमें मध्य प्रदेश कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन का सहयोग प्राप्त हो रहा है। हम अपने सारे सदस्यों से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। यह मीटिंग 16/17 दिसम्बर, 2016 में रखी गई है जहाँ आप सबका पहुँचना बहुत जरूरी है। हम इस मीटिंग की सूचना इस पत्रिका के माध्यम से व ई मेल के माध्यम से ही दे पाएंगे। वैसे प्रयत्न रहेगा की हर एक को



अलग-अलग पत्र भी लिखे परन्तु हम चाहते हैं, कि हमारे सदस्य इस सूचना को ही निमन्त्रण समझे। एसोसिएशन का कोई भी कार्य उनका अपना कार्य होता है।

फेडरेशन वा कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की मीटिंग 17 तारीख को रखी गई है। इस में शीतगृह उद्योग के बारे में विशेष चर्चा होगी। पूरा साल कैसा रहा? नए शीतगृह कहाँ और कितने आ रहे हैं? आलू का उत्पादन सामान्य रूप से कैसे चल रहा है? शीतगृह उद्योग किस दिशा में और कितनी प्रगति कर रहा है? आदि विषयों पर चर्चा होगी। 16 तारीख को विशेष कर के National Center for Cold Chain Development, Department (NCCD)/ NABARD/Food Processing वा Solar Energy चर्चा के विषय रखे गए हैं। इस में विशेषतः सरकार की नई पॉलिसी जो शीतगृहों के बारे में है आ गई है या आने वाली है के बारे में प्रकाश डाला जायेगा, जिसे National Centre for Cold Chain Development, (NCCD)/ NABARD के अधिकारी विशेष कर बतायेंगे।

इस तरह का ज्ञानवर्धक Session 11.30 बजे चालू हो जायेगा। इससे पहले ICE Company वाले अपने द्वारा लगाई गई Exhibition का उद्घाटन करेंगे। यह Exhibition भी देखने काबिल होगी। आपको पता लगेगा कि आपको नई कौन सी मशीनें आपके जरूरत की हैं, किस भाव पर और कहाँ मिल रही हैं?

कोशिश तो पूरी करी जा रही है कि एक गुलदस्ते की भांति सजा कर सारे भारत से आने वाले शीतगृहस्वामियों को कोई उनके मतलब की शिक्षा के रूप में कीमती भेट दी जाये। बस आप के सहयोग की आवश्यकता है। हमें आपका वहाँ पहुँचना सबसे बड़ा सहयोग होगा। हमें पत्र द्वारा अवश्य सूचित करे की आप किस तरह का और सहयोग कर सकते हैं।

इस मीटिंग में विभिन्न Embassy जैसा Netherland, France, Spain, U.S.A, Germany आदि को संपर्क किया जा रहा है जिससे की उनके देशों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर आकर उनके द्वारा की गई प्रगति वा उनके यहाँ बिकने वाली मशीनरी के बारे में बताए।

इन्दौर की मीटिंग का खर्च इस प्रकार होगा :

ठहरने की जगह : Brilliant Convention Centre Nakshatra
Plot No : 5, Part II, Scheme 78,
Near Life Care Hospital, Vijaynagar,
Indore – 452010 (Madhya Pradesh)

मीटिंग का स्थान : Orion Hall

नोट : नशत्र में ठहरने वाले सदस्य जो कि फेडरेशन में वहाँ पहुँच कर अपने आपको Register करायेंगे उनको दो रात के ठहरने के मात्र 6000 रूपए प्रति व्यक्ति देने होंगे जिसमें 5500 रूपए 2 रात कमरे में ठहरने का वा 500 रूपए Registration Fees का देय होगा। यहाँ पर उन्हें एक कूपन भी दी जायेगी जिससे उन्हें वहाँ पर मीटिंग में होने वाले लंच डिनर वा चाय का कुछ भी देय नहीं



होगा। अच्छा है कि आप 16 तारीख की सुबह अवश्य पहुँच जाए। 16 तारीख की सुबह नाश्ते की व्यवस्था नहीं होगी। 17 व 18 को नाश्ते की व्यवस्था रहेगी। 18 को नाश्ते के बाद से फेडरेशन का कार्यक्रम पूरी तरह समाप्त हो जाएगा। आपको 12 बजे दोपहर तक कमरा छोड़ना है। फेडरेशन की तरफ से खाने की व्यवस्था केवल उन सदस्यों के लिए होगी जो कि कनवेंशन सेन्टर में ठहर रहे हैं। वे सदस्य जो केवल रजिस्ट्रेशन करवाएंगे फेडरेशन की तरफ से कूपन नहीं पायेंगे। एक कमरे में दो व्यक्तियों के ठहरने की व्यवस्था की गई है।

कृपया अपने आने की सूचना शीघ्र-अति-शीघ्र भेजें और 6000 रूपए भेजकर कन्फर्म बुकिंग करवा लें।

हमें सूचना 15 नवम्बर तक अवश्य मिल जानी चाहिए, जिससे कि हम आपको जमा रुपयों की रसीद भेज सकें। उसी रसीद की कापी को जब आप Convention Centre में पहुँचे और फेडरेशन के आदमी को दिखाए तो आपको फौरन कमरे की व्यवस्था हो जाए। आपको परेशान ना होना पड़े। बुकिंग के लिए पैसे लखनऊ में देय, बैंक ड्राफ्ट, फेडरेशन ऑफ कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन ऑफ इण्डिया के पते पर भेज सकते हैं। या फिर फेडरेशन के Bank Account में जमा करा सकते हैं। Account Number इस प्रकार है :-

Bank Details

Bank Account : Savings Bank Account Number 680310100014689

Name of Account Holder : Federation of Cold Storage Associations of India

Address : C/o Swarup Cold Storage, Water Works, Road, Aishbagh, Lucknow (Uttar Pradesh) India Pin-226004

Bank address : Bank of India, Aishbagh Branch, Chandranagri, 278/81, Aishbagh Road, Lucknow (Uttar Pradesh) Pin-226004

IFSC : BKID0006803

यदि आप 6000 रूपए का भुगतान चेक द्वारा भेज रहे हैं तो यह पहली नवम्बर, 2016 तक हमें प्राप्त हो जाना चाहिए।

आलू का आचार :

हमें श्री हंसमुख जैन ने बड़ा ही दिलचस्प आलू का प्रयोग भेजा है। आशा है कि यह पढ़ने वालों को अच्छा लगेगा।

“आलू ऐसी चीज है जो हर घर में बनती है। सूखे मसाले के साथ, घी में सिर्फ हींग जीरे का तड़का लगाकर, ग्रेवी में या फिर बैंगन, पालक, मैथी या पुलाव में डालकर आलू उस सब्जी की वैरायटी बढ़ा देती है। आलू जिसमें डले उसके स्वाद, उसके रंग में रंग जाता है। हालांकि नेपाल में इसे बड़े अलग अंदाज में बनाते हैं। वे बनाते हैं आलू का आचार। इसमें आलू की अपनी



इंडिविजुअलिटी होती है। जो आलू के जेनुइन लवर्स हैं, उन्हें यह थॉट ही लगेगा। आज सिटी भास्कर के इस कॉलम में पहली बार इन्दौर के फूडीज से बात कर रहा हूँ और यह नेपाली रेसिपी भी शेयर कर रहा हूँ। असल में मेरी दादी नेपाली थीं। उन्हीं की बदौलत घर की रसोई में भारतीय मसालों के बीच नेपाली मसालों को जगह मिली और नेपालीज डिशेस में से यह मेरी वन ऑफ द फेवरेट है। हालांकि इसमें जो नेपाली मसाले पड़ते हैं उन्हें ढूँढने के लिए थोड़ी मशक्कत तो आपको करना पड़ेगी।

आलू का आचार बनाने के लिए नींबू के साइज के आलू उबालकर छील लें। बहुत बॉइल न करें। वरना आलू बिखर जाएंगे। हमें थोड़े हार्ड आलू ही चाहिए। इन्हें आधा काट लें। अब गिंगली सीड्स, जीरा और तिम्मूर को ड्राय रोस्ट करें। इन्हें थोड़े पानी के साथ ग्राइंड कर लें। अब कटे आलू सर्विंग डिश में ले लें। इनमें नमक और नींबू का रस मिलाएं। अब एक पैन में तेल गर्म करें और थोड़ी सौंफ डालें। ये क्रैकल करने लगे तब स्प्लिट की हुई हरी मिर्च डालें और एक मिनट के लिए कवर कर दें। अब इसमें हल्दी पाउडर डालें और जो टेम्परिंग तैयार की है वह आलू पर डाल दें। हरे धनिया से गार्निश कर अपनी चॉइस की ब्रेड के साथ इसे सर्व करें।”

विद्युत सम्बन्धी

वर्ष 2016-17 का नया टैरिफ प्रकाशित हो गया है जो कि 1.8.2016 से लागू है। इस टैरिफ में HV2 के उपभोक्ताओं के लिए दरों में कोई बढ़ोत्तरी नहीं हुई है।

रेगुलेटरी सरचार्ज 2 को जिसकी पूरे हट जाने की उम्मीद थी, अभी नहीं हटा है। रेगुलेटरी सरचार्ज 1 पहले ही हट चुका है। थोड़ा बहुत जो भी बदलाव हुआ है वह Steel Furnaces के रेट में है। यहाँ पर हम आप को HV2 का टैरिफ दे रहे हैं।

इस नए टैरिफ में दो तीन छोटी-छोटी ध्यान देने योग्य बातें हैं जैसे –

1. LMV 2 उपभोक्ताओं के लिए व्यापारिक संस्थान, जैसे दुकानें आदि के लिए यदि Roof Top Solar Power Grid लगाई जाए जो की net metering के साथ लगेगी, बिजली कम्पनी को मासिक न्यूनतम चार्ज देय नहीं होगा। Sr. No. 21 Tariff Order 2016-17 General Provisions.
2. यदि आप के बिजली के बिल में किसी भी तरह, आप का पैसा ज्यादा जमा हो गया है, जिसे आप लेने के हकदार है, उस पर आप Security पर मिलने वाले ब्याज के बराबर ब्याज के हकदार होंगे। Sr. No. 22 Tariff Order 2016-17 General Provisions
3. Rural Schedule की घोषणा समय समय पर State Load Despatch Centre (SLDC) Lucknow से की जायेगी। इनके द्वारा समय-समय पर दी गई परिभाषा के आधार पर ही Rural Schedule का फैसला होगा। Sr. No. 23 Tariff Order 2016-17 General Provisions
4. यहाँ पर चूँकि हमें Rural Tariff 2016-17 हिन्दी में नहीं मिला है। अतः अंग्रेजी में ही Print कर रहे हैं।



RATE SCHEDULE HV- 2
LARGE AND HEAVY POWER

1. APPLICABILITY:

This rate schedule shall apply to all consumers having contracted load above 75 kW (100 BHP) for industrial and / or processing purposes as well as to Arc / induction furnaces, rolling / re-rolling mills, mini-steel plants and floriculture & farming units and to any other HT consumer not covered under any other rate schedule.

Supply to Induction and Arc furnaces shall be made available only after ensuring that the loads sanctioned are corresponding to the load requirement of tonnage of furnaces. The minimum load of one-ton furnace shall in no case be less than 400 kVA and all loads will be determined on this basis. No supply will be given on loads below this norm.

For all HV-2 consumers, conditions of supply, apart from the rates, as agreed between the Licensee and the consumer shall continue to prevail as long as they are in line with the existing Regulations & Acts.

2. CHARACTER AND POINT OF SUPPLY:

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code.

3. RATE:

Rate, gives the demand and energy charges (including the TOD rates as applicable to the hour of operation) at which the consumer shall be billed for his consumption during the billing period applicable to the category:

(A) Urban Schedule:

	For supply up to and including 11 kV	For supply above 11 kV and up to & including 66 kV	For supply above 66 kV and up to & including 132 kV	For supply above 132 kV
BASE RATE				
Demand Charges	Rs. 250.00 / kVA / month	Rs. 240.00 / kVA / month	Rs. 220.00 / kVA / month	Rs. 220.00 / kVA / month
Energy Charges	Rs. 6.65 / kVAh	Rs. 6.35 / kVAh	Rs. 6.15 / kVAh	Rs. 5.95 / kVAh
TOD RATE				
*22:00 hrs – 06:00 hrs	(-) 7.5%	(-) 7.5%	(-) 7.5%	(-) 7.5%
06:00 hrs – 17:00 hrs	0%	0%	0%	0%
17:00 hrs – 22:00 hrs	(+) 15%	(+) 15%	(+) 15%	(+) 15%

(B) Rural Schedule :

This schedule shall be applicable only to consumers getting supply up to 11 kV as per 'Rural Schedule'. The consumer under this category shall be entitled to a rebate of 7.5% on demand & energy charges as given for 11 kV consumers under urban schedule without TOD rates.

(C) Consumers already existing under HV-2 category with metering arrangement at low voltage:

Existing consumer under HV-2 with metering at 0.4 kV shall be required to pay as per schedule applicable to 11 kV consumers under HV-2 category.

4. PROVISIONS RELATED TO SEASONAL INDUSTRIES :

Seasonal industries will be determined in accordance with the criteria laid down below. No exhaustive list can be provided but some examples of industries exhibiting such characteristics are sugar, ice, rice mill and cold storage. The industries which operate during certain period of the year, i.e. have seasonality of operation, can avail the benefits of seasonal industries provided:

- i. The continuous period of operation of such industries shall be at least 4 (four) months but not more than 9 (nine) months in a financial year.
- ii. Any prospective consumer, desirous of availing the seasonal benefit, shall specifically declare his season at the time of submission of declaration / execution of agreement mentioning the period of operation unambiguously.
- iii. The seasonal period once notified cannot be reduced during the next consecutive 12 months. The off-season tariff is not applicable to composite units having seasonal and other category loads.
- iv. The off-season tariff is also not available to those units who have captive generation exclusively for process during season and who avail Licensees supply for miscellaneous loads and other non-process loads.
- v. The consumer opting for seasonal benefit has a flexibility to declare his off seasonal maximum demand subject to a maximum of 25% of the contracted demand. The tariff rates (demand charge per kW / kVA and energy charge per kWh / kVAh) for such industries during off-season period will be the same as for normal period. Further, during the off season fixed charges shall be levied on the basis of maximum demand recorded by the meter (not on normal billable demand or on percentage contracted demand). Rates for the energy charges shall however be the same as during the operational season. Further, first violation in the season would attract full billable demand charges and energy charges calculated at the unit rate 50% higher than the applicable tariff during normal period but only for the month in which the consumer has defaulted. However, on second default the consumer will forfeit the benefit of seasonal rates for the entire season. →

5. FACTORY LIGHTING:

The electrical energy supplied shall also be utilized in the factory premises for lights, fans, coolers, etc. which shall mean and include all energy consumed for factory lighting in the offices, the main factory building, stores, time keeper's office, canteen, staff club, library, crèche, dispensary, staff welfare centres, compound lighting, etc. No separate connection for the same shall be provided.

11.2 RATE SCHEDULE FOR FY 2016-17

RETAIL TARIFFS FOR FINANCIAL YEAR 2016-17

GENERAL PROVISIONS:

These provisions shall apply to all categories unless specified otherwise and are integral part of the Rate Schedule.

1. NEW CONNECTIONS :

All new connections shall be given as per the applicable provisions of Electricity Supply Code and shall be released in multiples of KW only, excluding consumers under categories LMV-5 & LMV-8 of Rate Schedule. Further, for tariff application purposes, if the contracted load (kW) of already existing consumer is in fractions then the same shall be treated as next higher kW load.

2. READING OF METERS:

As per applicable provisions of Electricity Supply Code.

3. BILLING WHEN METER IS NOT MADE ACCESSIBLE:

A penalty of Rs. 50 / kW or as decided by the Commission through an Order shall be levied for the purposes of Clause 6.2 (c) of the applicable Electricity Supply Code.

4. BILLING IN CASE OF DEFECTIVE METERS:

As per the applicable provisions of Electricity Supply Code.

5. KVAH TARIFF:

'kVAh based tariffs' shall be applicable on all consumers having contracted load of 10 kW / 13.4 BHP and above, under different categories with TVM / TOD / Demand recording meters (as appropriate).

The rates prescribed in different categories in terms of kW and kWh will be converted into appropriate kVA and kVAh by multiplying Fixed / Demand Charges and Energy Charges by an average power factor of 0.90. Similarly, the Fixed / Demand Charges expressed in BHP can be converted into respective kVA rates in accordance with formula given below:



Demand Charges in kVA = (Demand Charges in BHP / 0.746) * 0.90

Demand Charges in kVA = (Fixed Charges in kW * 0.90)

Energy Charges in kVAh = (Energy Charges in kWh * 0.90)

Note : If the power factor of a consumer is leading and is within the range of 0.95 - 1.00, then for tariff application purposes such leading power factor shall be treated as unity. The bills of such consumers shall be prepared accordingly. However, if the leading power factor is below 0.95 (lead) then the consumer shall be billed as per the kVAh reading indicated by the meter. However, the aforesaid provision of treating power factor below 0.95 (lead) as the commensurate lagging power factor for the purposes of billing shall not be applicable on HV-3 category and shall be treated as unity. Hence, for HV-3, lag + lead logic of the meter should not be used and "lag only" logic of the meter should be provided which blocks leading kVARh thereby treating leading power factor as unity and registering instantaneous kWh as instantaneous kVAh in case of leading power factor.

6. BILLABLE LOAD / DEMAND:

For all consumers having TVM / TOD / Demand recording meters installed, the billable load / demand during a month shall be the actual maximum load / demand as recorded by the meter (can be in parts of kW or kVA) or 75% of the contracted load / demand (kW or kVA), whichever is higher.

Further in case the licensee fails to note the actual maximum load / demand reading or in case of spot-billing, then the consumer may approach the licensee with a photo of the actual maximum load / demand reading displayed on his meter of the previous month. The licensee shall accept the same for the purpose of computation of billable demand, however if the licensee wishes to, it can get the same verified within 10 days.

7. SURCHARGE / PENALTY:

(i) DELAYED PAYMENT:

If a consumer fails to pay his electricity bill by the due date specified therein, a late payment surcharge shall be levied at 1.25% per month; upto first three months of delay and subsequently @ 2.00% per month of delay. Late payment surcharge shall be calculated proportionately for the number of days for which the payment is delayed beyond the due date specified in the bill and levied on the unpaid amount of the bill excluding surcharge. Imposition of this surcharge is without prejudice to the right of the Licensee to disconnect the supply or take any other measure permissible under the law. →

(ii) CHARGES FOR EXCEEDING CONTRACTED DEMAND:

- a) If the maximum load / demand in any month of a domestic consumer having TVM / TOD / Demand recording meter exceeds the contracted load / demand, then such excess load / demand shall be levied equal to 100% of the normal rate apart from the normal fixed / demand charge as per the maximum load / demand recorded by the meter. Further, if the consumer is found to have exceeded the contracted load / demand for continuous previous three months, the consumer shall be served a notice of one month advising him to get the contracted load enhanced as per the provisions of UPERC Electricity Supply Code, 2005 and amendments thereof. However, the consumer shall be charged for excess load for the period the load is found to exceed the contracted load. The Licensee shall merge the excess load with the previously sanctioned load, and levy additional charges calculated as above, along with additional security. Subsequent action regarding the increase in contracted load, or otherwise shall be taken only after due examination of the consumer's reply to the notice and a written order in this respect by the Licensee.
- b) If the maximum load / demand in any month, for the consumers of other category(except (a) above) having TVM/ TOD /Demand recording meter exceeds the contracted load /demand , then such excess load /demand shall be levied equal to 200% of the normal rate apart from the normal fixed / demand charges as per the maximum load /demand recorded by the meter.
- c) Any surcharge / penalty shall be over and above the minimum charge, if the consumption bill of the consumer is being prepared on the basis of minimum charge.
- d) Provided where no TVM / TOD / Demand recording meter is installed, the excess load / demand penalty shall be billed as per the UPERC Electricity Supply Code, 2005 as amended from time to time.

8. POWER FACTOR SURCHARGE:

- i. Power factor surcharge shall not be levied where consumer is being billed on kVAh consumption basis.
- ii. It shall be obligatory for all consumers to maintain an average power factor of 0.85 or more during any billing period. No new connections of motive power loads / inductive loads above 3 kW, other than under LMV-1 and LMV-2 category, and / or of welding transformers above 1kVA shall be given, unless shunt capacitors having I.S.I specifications of appropriate ratings are installed, as described in ANNEXURE 11.4. ➔

- iii. In respect of the consumers with or without static TVMs, excluding consumers under LMV-1 category up to contracted load of 10 kW and LMV-2 category up to contracted load of 5 kW, if on inspection it is found that capacitors of appropriate rating are missing or in-operational and Licensee can prove that the absence of capacitor is bringing down the power factor of the consumer below the obligatory norm of 0.85; then a surcharge of 15% of the amount of bill shall be levied on such consumers. Licensee may also initiate action under the relevant provisions of the Electricity Act, 2003, as amended from time to time. Notwithstanding anything contained above, the Licensee also has a right to disconnect the power supply, if the power factor falls below 0.75.
- iv. Power factor surcharge shall however, not be levied during the period of disconnection on account of any reason whatsoever.

9. PROTECTIVE LOAD :

Consumers getting supply on independent feeder at 11kV & above voltage, emanating from sub-station, may opt for facility of protective load and avail supply during the period of scheduled rostering imposed by the Licensee, except under emergency rostering. An additional charge @ 100% of base demand charges fixed per month shall be levied on the contracted protective (as per Electricity Supply Code) load each month. However, consumers of LMV-4 (A) - Public Institutions will pay the additional charge @ 25% of base demand charges only. During the period of scheduled rostering, the load shall not exceed the sanctioned protective load. In case the consumer exceeds the sanctioned protective load during scheduled rostering, he shall be liable to pay twice the prescribed charges for such excess load.

10. ROUNDING OFF :

All bills will be rounded off to the nearest rupee i.e. up to 49 paisa shall be rounded down to previous rupee and 50 paisa upwards shall be rounded up to next rupee. The difference due to such rounding shall be adjusted in subsequent bills.

11. OPTION OF MIGRATION TO HV-1 & HV-2 CATEGORY :

The consumer under LMV-2 and LMV-4 with contracted load above 50 kW and getting supply at 11 kV & above voltage shall have an option to migrate to the HV-1 category and LMV-6 consumers with contracted load above 50 kW and getting supply at 11 kV & above voltage shall have an option to migrate to the HV-2 category. Furthermore, the consumers shall have an option of migrating back to the original category on payment of charges prescribed in Cost Data Book for change in voltage level. →

12. PRE-PAID METERS / AUTOMATIC METER READING SYSTEM:

- (i) Any consumer having prepaid meters shall also be entitled to a discount of 1.25% on Rate as defined in the Tariff Order.
- (ii) The token charges for code generation for prepaid meters shall be Rs. 10/- per token or as decided by the Commission from time to time.

13. CONSUMERS NOT COVERED UNDER ANY RATE SCHEDULE OR EXPRESSLY EXCLUDED FROM ANY CATEGORY :

For consumers of light, fan & power (excluding motive power loads) not covered under any rate schedule or expressly excluded from any LMV rate schedule will be categorized under LMV-2.

- 14. A consumer under metered category may undertake any extension work, in the same premises, on his existing connection without taking any temporary connection as long as his demand does not exceed his contracted demand and the consumer shall be billed in accordance with the tariff applicable to that category of consumer.

15. SOLAR WATER HEATER REBATE :

If consumer installs and uses solar water heating system of 100 litres or more, a rebate of Rs. 100 /- per month or actual bill for that month whichever is lower shall be given. The same shall be subject to the condition that consumer gives an affidavit to the licensee to the effect that he has installed such system and is in working condition, which the licensee shall be free to verify from time to time. If any such claim is found to be false, in addition to punitive legal action that may be taken against such consumer, the licensee will recover the total rebate allowed to the consumer with 100% penalty and debar him from availing such rebate for the next 12 months.

16. REBATE ON PAYMENT ON OR BEFORE DUE DATE:

A rebate at 0.50% of Rate shall be given in case the payment is made on or before the due date. The consumers having any arrears in the bill shall not be entitled for this rebate. The consumers who have made advance deposit against their future monthly energy bills shall also be eligible for the above rebate applicable on Rate.

17. REBATE TO CONSUMERS WHO SHIFT FROM UNMETERED TO METERED CONNECTION :

In case any rural consumer shifts from unmetered to metered category, he shall be entitled to rebate of 10% on Rate which shall be applicable from date of installation of meter till end of FY 2017-18.



18. SCHEME FOR ADVANCE DEPOSIT FOR FUTURE MONTHLY ENERGY BILLS :

If a consumer intends to make advance deposit against his future monthly energy bills, the Licensee, shall accept such payment and this amount shall be adjusted only towards his future monthly energy bills. On such advance deposit the consumers shall be paid interest, at the interest rate applicable on security deposit, for the period during which advance exists for each month on reducing balance method and amount so accrued shall be adjusted in the electricity bills which shall be shown separately in the bill of each month. Further, quarterly report regarding the same must be submitted to the Commission.

19. FACILITATION CHARGE FOR ONLINE PAYMENT :

- (i) No transaction charge shall be collected from the consumers making their payment through internet banking.
- (ii) The Licensees shall bear the transaction charges for transactions up to Rs. 4,000 for payment of bill through internet using Credit Card / Debit Card.

20. MINIMUM CHARGE :

Minimum charge is the charge in accordance with the tariff in force from time to time and come into effect only when sum of fixed / demand charges and energy charges are less than a certain prescribed amount i.e. Minimum Charges. For each month, consumer will pay an amount that is higher of the following:

- Fixed / Demand charges plus Energy Charge on the basis of actual consumption for the month and additional charges such as Electricity Duty, Regulatory Surcharges, FPPCA Surcharges and any other charges as specified by the Commission from time to time.
- Monthly minimum charge as specified by the Commission and computed at the contracted load and additional charges such as Electricity Duty, Regulatory Surcharges, FPPCA Surcharges and any other charges as specified by the Commission from time to time.

21. EXEMPTION FROM MINIMUM CHARGE FOR USING SOLAR POWER :

If a consumer under LMV-2 (Non domestic light, fan and power) category installs a rooftop solar plant under the provisions of UPERC (Rooftop Solar PV Grid Interactive Systems Gross / Net Metering) Regulations, 2015 with maximum peak capacity of the grid connected rooftop solar PV system not exceeding 100% of the sanctioned connected load / contract demand of the consumer, then such consumer shall be exempted from payment of monthly minimum charges. Such exemption shall be in force till the time the solar plant remains fully operational. →

22. INTEREST ON DUES PAYABLE TO CONSUMER BY THE LICENSEE :

If a consumer becomes eligible for dues from the Licensee which may arise out of rectification / adjustment / settlement of bill(s), then such consumer will also be entitled to get interest at an interest rate applicable for interest on security deposits on all the dues payable by the Licensee to the consumer.



The Licensee shall compute the interest amount for the period during which such pending amounts exist and adjust such interest towards the future monthly bills of consumers. After adjustment of the interest amount in a particular month, the balance amount, will be carried forward to next month for adjustment with interest on balance amount. The details of such interest amount and adjustment made during the month shall be shown separately in the bill. Further, separate accounting of interest paid must be maintained by the Licensees.

23. DEFINITION OF RURAL SCHEDULE:

Rural Schedule means supply schedule as defined and notified by State Load Despatch Centre (SLDC), Lucknow from time to time.

सेवा में,

Postal Registration No.SSP/LW/NP65/2014-16

.....
.....

प्रकाशक, मुद्रक, सम्पादक एवं स्वामी महेन्द्र स्वरूप, कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश,
स्वरूप कोल्ड स्टोरेज, वाटर वर्क्स रोड, ऐशबाग, लखनऊ से प्रकाशित एवं
रोहिताश्व प्रिण्टर्स, ऐशबाग रोड, लखनऊ द्वारा मुद्रित